भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 255

02.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक बसें

255. **श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः**

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पीएम ई-ड्राइव योजना के दूसरे चरण में मुंबई को एक हजार और पुणे को आठ सौ इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि निर्धारित/स्वीकृत/जारी की गई है;

(ग) ये इलेक्ट्रिक बसें इन शहरों में कब तक चलने लगेंगी;

(घ) दूसरे चरण के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अन्य शहरों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का इस पहल के तहत राज्य ट्रांसपोर्ट कंपनियों या प्राइवेट ऑपरेटरों के साथ कोई सहयोग करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन शहरों में ई-बस के बेड़े के लिए पर्याप्त चार्जिंग अवसंरचना, उचित रखरखाव सहायता और दीर्घकालिक परिचालन सततता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम के दूसरे चरण के आवंटन में, मुंबई के लिए 1500 ई-बसें और पुणे के लिए 1000 ई-बसें आवंटित की गई हैं।

(ख) और (ग) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 14,028 ई-बसों के संचालन के लिए ₹4,391 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। 10,900 ई-बसों के पहले चरण के आवंटन के लिए ई-बस परिचालकों के चयन हेतु बोली 14/11/2025 खोली गई हैं।

(घ) : मुंबई और पुणे के अलावा, दूसरे चरण में पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत हैदराबाद और अहमदाबाद प्रत्येक को 200 ई-बसें आवंटित की गई हैं।

(ड़.) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ई-बसों के लिए सहायता राज्य/शहर परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) को परिचालन व्यय (ओपेक्ष)/ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर प्रदान किया जाता है। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से समेकन मॉडल पर ई-बसों की खरीदारी सीईएसएल द्वारा की जाती है। सीईएसएल द्वारा जारी निविदा (आरएफपी) में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली निजी संस्थाएँ ई-बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव में भाग ले सकती हैं।

(च) : जीसीसी मॉडल के तहत, चयनित निजी ऑपरेटर बसों की खरीद, आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के साथ-साथ चार्जिंग के लिए मेंटेनेंस डिपो में संबंधित विद्युत और सिविल अवसंरचना के विकास और रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होता है।

.

****